

महेश जोशी समेत आधा दर्जन आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं आरोपी

-कार्यालय संवाददाता- **जयपुर।** राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और पूर्व आईएसएस सुबोध अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों संजय बडाय़ा, महेंद्र प्रकाश सोनी, कृष्णदीप गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार और मुकेश पाठक की जमानत याचिकाओं पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। इसके साथ ही अदालत में मामले में

अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली ने यह आदेश आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। जमानत याचिका में महेश जोशी की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब डेढ साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं अप्रैल, 20२5 से दिसंबर, 20२5 तक इंडी से जुड़े मामले में अभिरक्षा में रहने के दौरान एसीबी ने उसे अभिरक्षा में लेने

का प्रयास नहीं किया गया। वह संबंधित टेंडर में बिड एवैल्युशन कमेटी व वित्त समिति का सदस्य भी नहीं था। टेंडर से जुड़ा सारा काम प्रशासनिक अधिकारियों ने किया था। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। वहीं विभाग के तत्कालीन एसई महेंद्र प्रकाश सोनी की ओर से अधिवक्ता सुधीर जैन ने कहाकि मामले में समान तथ्यों के आधार पर एक से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा टेका फर्म के संचालकों को पूर्व में राहत दी गई है। एसीबी ने मामले में आरोप

पत्र भी पेश कर दिया है। जिसकी सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि तत्कालीन मंत्री होने के नाते आरोपी विभाग का मुखिया था और अन्य आरोपियों से मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऊँची दरों पर टेंडर जारी किए गए। ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पतंजलि योगपीठ में जड़ी-बूटी दिवस के रूप में मनाया आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिवस

हरिद्वार। पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिवस जड़ी-बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने कहा कि पतंजलि अनुसंधान संस्थान ने आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जन्मदिन केवल उत्सव नहीं, बल्कि श्रेष्ठ कार्यों का संकल्प लेने का दिन है। कार्यक्रम में साक्ष्य आधारित 1२ नई आयुर्वेदिक औषधियों और आचार्य बालकृष्ण द्वारा रचित 40 पुस्तकों का विमोचन किया गया।

स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सहित करीब 7१0 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं, पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर



अस्पताल की ओर से करीब 1,5०0 लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और औषधियां वितरित की गईं। कार्यक्रम में जड़ी-बूटियों के महत्व

के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नीम, तुलसी, एलोवेरा और आंवला सहित औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया गया।

4 दिन में 100 ई-रिक्शा का पंजीयन नहीं हो सका

जयपुर। राजधानी में परकोटे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करने के लिए शुरु की गई ई-रिक्शा की जोनवार पंजीयन व्यवस्था को अपेक्षित गति नहीं मिल रही है।

एक अगस्त से शुरु हुई पंजीयन प्रक्रिया के चार दिन बाद भी 1०0 का आंकड़ा नहीं छू सकी है। अब तक करीब 3०0 से अधिक लोगों ने जानकारी ली है, लेकिन केवल करीब 5० ई-रिक्शा का ही पंजीयन हो पाया है।

इस स्थिति को देखते हुए यातायात पुलिस ने डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय (यादगार) में ई-मित्र सुविधा केंद्र शुरु किया है, जहां ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन माध्यम से भी पंजीयन कराया जा रहा है।

जनजातीय अंचलों में 3७ लाख लोगों की स्क्रीनिंग

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय अंचलों में सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी के नियंत्रण और रोकथाम के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। सरकार का फोकस केवल बीमारी की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्क्रीनिंग से लेकर समयबद्ध उपचार, नियमित फॉलोअप, टीकाकरण, काउंसलिंग और जागरूकता तक एक समग्र स्वास्थ्य सुرخ्शा तंत्र विकसित करने पर है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन-2०47 के अनुरूप राजस्थान सरकार का लक्ष्य सिकल सेल

एनीमिया से लड़ने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में मजबूत स्वास्थ्य सुर्क्षा तंत्र तैयार कर आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी के दुष्प्रभाव से बचाना है। प्रदेश में जनजातीय अंचलों की करीब 37.५० लाख आबादी की स्क्रीनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में ३7.०2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर 98.72 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्क्रीनिंग के इस व्यापक अभियान के तहत उदयपुर में 11.12 लाख, बांसवाड़ा में 1०.39 लाख, डूंगरपुर में 8 लाख, प्रतापगढ़ में 4.26 लाख, सिरोही में 1.64 लाख, बारां में 9० हजार, पाली में 41 हजार, चित्तौडगढ़ व

राजसमंद में 1३-13 हजार लोगों की स्क्रीनिंग की गई है।

उदयपुर के सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की प्रभावशीलता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक यहाँ 6१6० ओपीडी और 3०6 आईपीडी सेवाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं तथा 589 सिकल सेल रोगियों और 3०0० सिकल सेल वाहकों की पहचान हुई है।

इस केंद्र द्वारा 32 हजार नवजात की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 621 नवजात पॉजिटिव पाए गए। इसी प्रकार 85०० गर्भवती महिलाओं की एएनसी स्क्रीनिंग में 5०० पॉजिटिव मामलों की पहचान की गई।

पेड़ लगाने के बाद उनका संरक्षण भी करें : बागड़े स्कूलों में नामांकन वृद्धि पर चर्चा

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को लोकभवन में ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गांवों के प्रभावी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, लक्ष्मी दीदी और वीबी-जीरामजीके तहत राजस्थान में हुए कार्यों के प्रस्तुतीकरण को देखकर इनके तहत रही उपलब्धियों की विशेष रूप से सरहाना की राज्यपाल ने गांवों में हस्तकलाओं, कौशल विकास से जुड़े कार्यों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने का आह्वान किया।



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे

राज्यपाल ने लखपति दीदी योजना, हर घर नल, सभी गांवों में शतप्रतिशत शौचालय के अंतर्गत हुए कार्यों की भी बैठक में विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने जीरामजी के अंतर्गत लोगों की

काम देने और इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने पर भी जोर दिया।

बागडे ने मानसून में अधिक से अधिक पौधारोपण किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाएं ही नहीं, यह भी सुनिश्चित करें कि वे लगने के बाद जिंदा रहे।

उन्होंने राजसमंद के पिपलांत्री गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से वहां पौधे लगाए गए हैं और उनका संरक्षण किया गया है, उसी तरह दूसरे गांवों में भी वृक्षारोपण के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने गांवों में पीने के पानी की प्रभावी व्यवस्था करने पर भी जोर दिया।

स्कूलों में नामांकन वृद्धि पर चर्चा

जयपुर (कासं)। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग एगशन प्लान तैयार करने में जुटा है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में मिशन पढ़ो राजस्थान, नामांकन वृद्धि, ड्राफ़्टआउट नियंत्रण, विद्यालय सुधार, सुरक्षा एवं मासिक रैंकिंग सहित विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिश-निर्देश दिए। रीड-ए-थॉन में लगभग 68 लाख लोगों की भागीदारी पर बधाई दी।

राजस्थान में 1 करोड़ हेक्टेयर फसली क्षेत्र का बीमा हुआ

जयपुर।। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सबसे ज्यादा 1 करोड़ हेक्टेयर फसली क्षेत्र का बीमा “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के तहत हुआ है। इसके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को हुए नुकसान की स्थिति में लाखों किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। राजस्थान में देश में सबसे अधिक लगभग 62 लाख 58 हजार किसानों को योजना में नामांकित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2०२५-२६ में राज्य के लगभग 2 करोड़ 82 लाख हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को योजना के अंतर्गत बीमित किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य के कुल फसली क्षेत्र में बीमित क्षेत्र 36 प्रतिशत है, जो देश के औसत 32 प्रतिशत से बेहतर है। यह प्रतिशत झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद सबसे अधिक है।

विधानसभा के षष्ठम सत्र से पहले देवनानी ने 1८ अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक

2० अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसूत्र सत्र, इससे पूर्व सभी पक्षों से होगी चर्चा

-विधानसभा संवाददाता- **जयपुर।** राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के षष्ठम सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक 18 अगस्त को प्रातः 1१ बजे विधानसभा में बुलाई है। उल्लेखनीय है कि सोलहवीं विधान सभा का षष्ठम सत्र 2० अगस्त से आरम्भ हो रहा है। सोलहवीं राजस्थान के स्पीकर वासुदेव देवनानी को यह पहल राजस्थान विधान सभा में ऐतिहासिक है। देवनानी राजस्थान के पहले स्पीकर हैं, जिन्होंने सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देवनानी ने कहा कि सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्थल है। इस स्थल की गरिमा को बनाए रखना सभी दलों के विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सदन को शांतिपूर्ण चलाने में सर्वदलीय बैठक अहम कदम है। देवनानी ने बताया है कि बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री भजन

विधानसभा प्रश्नकाल के लिए सरकार की नई रणनीति

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सौंपी विभागवार जिम्मेदारी

-विधानसभा संवाददाता- **जयपुर।** राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्रों को लेकर मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए अपने अधीन आने वाले विभिन्न विभागों के विधानसभा प्रश्नों एवं संसदीय कार्यों का दायित्व मंत्रियों के बीच विभाजित कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य प्रश्नकाल के दौरान विभागीय जवाबदेही को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाना है।

जारी आदेश के अनुसार उपमुख्यमंत्री दीपा कुमारी को आयोजना विभाग, आयोजना (जनशक्ति) तथा सांख्यिकी विभाग से जुड़े विधानसभा प्रश्नों और संसदीय कार्यों का दायित्व सौंपा गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह को खान एवं पेट्रोलियम, मत्स्य, राजकीय उपक्रम, अप्रवासी भारतीय, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता, इंदिरा गांधी नहर, आबकारी तथा कारागार विभागों से संबंधित प्रश्नों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के अधीन यदि कोई अन्य विभाग रहेगा तो उससे जुड़े प्रश्नों का उत्तरदायित्व भी गजेन्द्र सिंह के पास रहेगा।

संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल को कार्मिक, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, सामान्य प्रशासन, सम्पदा, निर्वाचन, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, मुद्रण एवं

लेखन सामग्री तथा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को सूचना एवं जनसंपर्क, शांति एवं अहिंसा, कृषि विपणन, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, श्रम तथा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभागों का दायित्व सौंपा गया है। वहीं राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम को गृह विभाग, प्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) तथा जेल विभाग से जुड़े विधानसभा प्रश्नों और संसदीय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का यह निर्णय विधानसभा के आगामी सत्र में प्रश्नकाल को अधिक प्रभावी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के जीवन पर पुस्तक का विमोचन

जयपुर। पांच राज्यों के राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सत्यपाल मलिक को प्रथम पुण्यतिथि पर बुधवार 5 अगस्त को कॉस्टीट्यूशनल क्लब राजस्थान विधानसभा में प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल कौर मलिक के द्वारा लिखित पुस्तक डियर सतपाल का विमोचन , हरिराम किंवाड़ा द्वारा बनाई गई सत्यपाल मलिक के जीवन दर्शन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म “द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया” का प्रसारण के साथ राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन हुआ । पुस्तक की समीक्षा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबोसी विभाग की सदस्य अंकांश जगखड़ ने की।

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शीलूड अवाडी शिक्षाविद् डॉ. गणेश नारायण गुरुजी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में राजस्थान विधानसभा में नेता दतिपक्ष टीकाराम जुली, गंगापुर से विधायक रामकेश मीणा, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, लाडनू विधायक मुकेश भाकर, चौमू विधायक डॉ. शिखा मील बराला, राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह, मुंडावर से विधायक ललित यादव, नोहर विधायक अमित चाचान, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे जस्साराम चौधरी मौजूद थे।

राजस्थान में इमर्सिव टूरिज्म एक्सपीरिएंस विकसित करने की जरूरत : शुचि त्यागी

जयपुर। पर्यटन सचिव शुचि त्यागी ने कहा कि, “आज के पर्यटक केवल पर्यटन स्थलों का भ्रमण नहीं, बल्कि यादगार और गहन अनुभवों की तलाश करते हैं। ऐसे में राजस्थान को निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ मजबूत सहयोग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले और इमर्सिव पर्यटन अनुभव विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कनेक्टिविटी और वन्यजीव, वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले प्रचार अभियानों के साथ राज्य पर्यटन को आर्थिक विकास के प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित करने पर जोर है। त्यागी बुधवार को जयपुर के आईटीसी राजपूताना में आयोजित



जयपुर स्थित आईटीसी राजपूताना में बुधवार को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के छठे संस्करण और प्रथम मारवाड़ ट्रेवल मार्ट जोधपुर का कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित हुआ।

राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आरडीटीएम) के छठे संस्करण और प्रथम मारवाड़ ट्रेवल मार्ट, जोधपुर के

कर्टेन रेजर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पर्यटन राजस्थान

हिस्ट्रीशीटर दंपत्ति के अवैध तीन मंजिला मकान पर चला बुलडोजर

-कार्यालय संवाददाता- **जयपुर।** राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हार्डकोर अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जयपुर दक्षिण जिले की मानसरोवर थाना पुलिस और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर दंपत्ति के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस के अनुसार ध्वस्त की गई तीन मंजिला अवैध इमारत की बाजार कीमत करीब एक करोड़ रुपए आंकी गई है।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजेश राज ने बताया कि मानसरोवर थाना क्षेत्र के गुर्जर की थड़ी स्थित शिव शंकर विहार में हिस्ट्रीशीटर मुकेश सांसी (49) और उसकी पत्नी तीजा देवी (45) ने कथित रूप से अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से जेडीए की अनुमति लिए बिना तथा भवन बायलॉज का उल्लंघन करते हुए मकान संख्या 36ए और 37 पर तीन मंजिला निर्माण करा रखा था। पुलिस के अनुसार क्षेत्र के लोगों द्वारा अवैध निर्माण का विरोध किए जाने पर आरोपी उन्हें डर्राकर-धमकाकर क्षेत्र में खीफ का माहौल बनाते थे।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त (मानसरोवर)



जयपुर पुलिस और जेडीए टीम ने बुधवार को मानसरोवर क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर दंपत्ति के अवैध मकान को ध्वस्त किया।

हेमेंद्र शर्मा के पर्यवेक्षण में मानसरोवर थानाधिकारी सतीश चंद के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस और जेडीए की संयुक्त टीम ने समन्वित कार्रवाई करते हुए मकान संख्या 36ए पर किए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहीं मकान संख्या 37 के संबंध में जेडीए ने धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया है।

पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीटर तीजा देवी के खिलाफ मानसरोवर

थाने में कुल 12 मामले दर्ज हैं। इनमें 9 मामले अवैध शराब तथा 3 मामले एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हैं। इनमें से 1१ मामलों में न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, जबकि एक मामला विचारोन्धी है। वहीं मुकेश सांसी के खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 6 मामले अवैध शराब तथा 2 मामले एनडीपीएस एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित हैं।